

आर.पी.एस.सी. बताए भर्ती प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक की कितनी शिकायतें मिली : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में बुधवार को याचिकाकर्ता पक्ष की बहस पूरी हो गई है। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को बहस जारी रखी जाएगी। वहीं अदालत ने आरपीएससी के अधिवक्ता एमएफ नेमा को यह बताने को कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान आयोग को पेपर लीक को लेकर कितनी शिकायतें मिली। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

■ याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा कि परीक्षा की तीनों पारियों के पेपर लीक हुए थे और उसी दिन पूरे प्रदेश में 11 एफ.आई.आर. दर्ज हो गई थी। इसके बावजूद आर.पी.एस.सी. की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई

■ याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि इस परीक्षा के दौरान कोई फोन के जैमर इस्तेमाल नहीं किये गये थे, जो ऐसी परीक्षाओं में किया जाना आम बात है। इसके अलावा परीक्षा में वीडियोग्राफी भी नहीं की गई थी

कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने अदालत को बताया कि हाल ही में ईओ-आरओ भर्ती परीक्षा की जांच के दौरान केवल तीन एफआईआर दर्ज की थी जिसके बाद पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एफआईआर भर्ती परीक्षा के दौरान कोई फोन के जैमर इस्तेमाल

नाटकीय रूप से इसे तीन दिन कर दिया गया और फिर संपागोय जिलों के बाहर जाकर नये परीक्षा केंद्र बनाये जो कि नियम विरुद्ध था, बल्कि ऐसे ही एक परीक्षा केंद्र जो पाली में स्थित है में पेपर लीक होने और चीटिंग के आरोप लगाते हुए एक एफआईआर भी दर्ज की गई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इन सभी तथ्यों को वजह से आरपीएससी का पेपर लीक में भूमिका और भी संदिग्ध होती है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि पेपर लीक के कारण कई ऐसे अभ्यर्थी का चयन किया गया है जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है या उनके माता-पिता अपराधी रहे हुए हैं या अपराधी संगठन से तालमेल रखते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जहां दार्जी अभ्यर्थियों को चिन्तित नहीं किया जा सकता, उस स्थिति

में भर्ती को रद्द किया जा सकता है। ऐसे में भर्ती को रद्द किया जाए।

दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विजान शाह ने बताया कि याचिका कई महीनों बाद दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं में से कुछ लिखित परीक्षा में फेल हुए, कुछ फिजिकल के बाद बाहर किए गए और कई साक्षात्कार में अंक नहीं ला पाए। यदि याचिकाकर्ता पास हो जाते तो फिर याचिका पेश नहीं की जाती। इसके अलावा एक याचिकाकर्ता तो एसओजी में ही कॉन्स्टेबल पद पर कार्यरत है, लेकिन इनकी जानकारी नहीं दी गई। सुनवाई के दौरान अदालती समय समाप्त होने के कारण अदालत ने प्रकरण को सुनवाई गुरुवार को तय की है।

आर.पी.सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो सरकार के जवाब देने के बाद पुनः जवाब पेश करेंगे।

जयपुर-आभानेरी-भानगढ़ यात्रा के पोस्टर का विमोचन



उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन राजस्थान के प्रतिनिधियों के साथ जयपुर-आभानेरी-भानगढ़-जयपुर यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया।

जयपुर। होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन राजस्थान के प्रतिनिधियों ने पर्यटन सचिव रवि जैन से मुलाकात कर जयपुर-आभानेरी-भानगढ़-जयपुर यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया। जयपुर-आभानेरी-भानगढ़-जयपुर की यात्रा में पर्यटकों को 1 दिन के टूर में आभानेरी-चाँद बावड़ी, हर्षत माता मंदिर, आभानेरी विलेज के साथ लंच शाहपुर आभानेरी रिसोर्ट में करवाया जायेगा। इसके साथ विश्व प्रसिद्ध भानगढ़ किले का इतिहास भी बताया जायेगा। इस टूर में गाइड भी साथ

रहेगा। इस टूर में प्रति व्यक्ति 2750 रूपए खर्च होगा। पोस्टर विमोचन के दौरान होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन राजस्थान अध्यक्ष तरुण कुमार बंसल, अधिराज सिंह शाहपुरा, सचिव, कुलदीप सिंह चंदेला, अध्यक्ष, असीम पारख, कोषाध्यक्ष, हुसैन खान, अध्यक्ष रणविजय सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कौशल राठौड़, उपस्थित थे अधिराज सिंह ने बताया कि इस यात्रा के दौरान जो पर्यटक खुद के व्हीकल से नहीं जा सकते या उसका बजट नहीं है कि वो पर्यटन कार वहन कर सके उनके लिए ये यात्रा है तथा उनके बजट में यह यात्रा सही है। जयपुर आने वाले

पर्यटक एक दिन ज्यादा ठहराव करेंगे जिससे जयपुर में होटलों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। इस यात्रा से घरेलू कलाकार, दुकानदार को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण लोगों को रोजगार भी उपब्ध होगा। आने वाले दिनों में जयपुर-पुष्कर-जयपुर एवं जयपुर-सांभर-जयपुर के बीच में भी इस तरह कि यात्रा को शुरूआत करेंगे। इस पोस्टर के विमोचन के दौरान पर्यटन सचिव ने धन्यवाद दिया। दिया कुमारी ने इसे सराहनीय कदम बताया जिससे राजस्थान के पर्यटन में इजाफा होगा तथा जयपुर के आरपास पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी।

भाजपा सरकार में किसी भी विधायक-मंत्री का कोई फोन टैप नहीं हुआ : बेदम

जयपुर। गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेदम ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने ओडी राजनीति शुरू कर दी है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपसी मामला है और मामला भी एक झूठी खबर का है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब किरोड़ी लाल मीणा ने दे दिया, उन्होंने बता दिया कि उनका कोई फोन टैप नहीं हुआ और मैं गृह राज्यमंत्री के तौर पर कहता हूँ कि हमारी सरकार में किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के फोन टैप नहीं हुए।

■ गृह राज्यमंत्री का कांग्रेसी नेता सचिन पायलट के बयान पर पलटवार

■ 'राज्य सरकार के एक साल के सुशासन को देखकर कांग्रेस घबराई'

रूप से प्रेस के सामने आकर भी कहा था कि उनके फोन टैप हो रहे हैं। उस समय अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर कांग्रेस के नेता हथमलावर थे लेकिन चुप रहे और बाद में गलतबर्हिया भर रहे थे। गृह राज्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी

कमियों से बचने के लिए सदन में मुख्यमंत्री का राज्यपाल के अधिभाषण पर जवाब बाधित करने का षडयंत्र किया। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के 1 साल के सुशासन की बात जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखी। बेदम ने कांग्रेस के नेताओं को इस ओडी राजनीति को बंद करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और इसी कारण उपचुनाव में आपका पता भी साफ कर दिया। फिर भी कांग्रेस के लोग बयानबाजी करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता गुमराह नहीं होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राजस्थान के विकास को देखकर जनता कांग्रेस को पूरी तरह नकार चुकी है।

बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा आमजन : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक बैंक रहित परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन की शुरुआत की और इसका परिणाम यह हुआ कि जनवरी 2025 तक देशभर में 54.58 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए। इनमें 55 प्रतिशत खाता धारक महिलाएँ हैं। मोदी सरकार की ओर से विभिन्न वंचित वर्गों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, स्टैट-डै आर इंडिया और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी कई योजनाओं को शुरू किया।

डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने स्वीकारी अपनी गलती

जयपुर। फोन टैपिंग मामले पर अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा करने वाले कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नोटिस मिलने के साथ अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से दिए नोटिस के जवाब में मीणा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। बुधवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री किरोड़ी मीणा ने अपने नोटिस और कांग्रेस के हंगामे पर जवाब दिया। नोटिस में क्या जवाब दिया, ये किरोड़ी ने नहीं बताया लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उनसे अनुशासनहीनता हुई है, जिसकी वजह से पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस दिया। गौरतलब है कि किरोड़ी लाल मीणा को भाजपा ने अनुशासनहीनता का सोमवार को नोटिस जारी किया था। वहीं, बुधवार को मीणा ने नोटिस का जवाब संघटन को भेज दिया है। मीणा ने कहा कि मेरे से जो गलती हुई है, नोटिस में वह दर्शाई हुई है। गलती हुई थी, उसका जवाब दे दिया है। किरोड़ी

■ 'अनुशासन तोड़ा तो नोटिस मिला, मैंने नोटिस का जवाब दे दिया'

ने इस दौरान फिर से कहा कि वह पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, तभी पार्टी ने उनको टिकट दिया है और तभी वे विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं। उधर पार्टी से नाराजगी के सवाल पर किरोड़ी लाल ने कहा कि नाराजगी तो उनकी पत्नी गोलमा देवी से भी हो जाती है। गोलमा देवी यह कहती हैं कि तुम चुप रहा करो, ज्यादा मत बोला करो, फिर भी मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। किरोड़ी मीणा ने इस दौरान विधानसभा सत्र में शामिल नहीं होने पर बीमारी का हवाला दिया और साथ ही कहा कि जब बीमारी सही हो जाएगी तो वह विधानसभा सत्र में शामिल होंगे। नोटिस से संतुष्ट नहीं होने के सवाल पर किरोड़ी लाल ने कहा कि मैंने क्या जवाब दिया, वह नहीं बताऊंगा। मेरी

राजस्थान पर्यटन नीति और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को बनया जा रहा है आसान : दिया कुमारी

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि राजस्थान पर्यटन नीति और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को आसान बनाया जा रहा है। इससे पर्यटन और फिल्म पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 8 व 9 मार्च को आई आई एफ ए 25 पुरस्कार समारोह आयोजित होना है, इससे राजस्थान पर्यटन को विश्व में भव्य पहचान मिलेगी। इससे राजस्थान में फिल्मों की शूटिंग्स में भी बढ़ोतरी होगी।

उन्होंने कहा राजस्थान पर्यटन का वैश्विक स्तर पर सशक्त ब्रांडिंग हो इस पर दोनों ही नीतियों में फोकस किया जाए। दिया कुमारी ने कहा कि पर्यटन नीति के द्वारा सेगमेंटवाइज नवाचार किए जाए जिससे पर्यटन से जुड़ी इकड़याँ और स्टैकहोल्डर्स तथा अन्य सभी राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने में अपना अधिकतम योगदान दें सके। उन्होंने कहा कि पर्यटन नीति में डिजिटल इनीशिएटिव को भी शामिल किया जाए।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शासन सचिव पर्यटन विभाग रवि जैन एवं पर्यटन आयुक्त विजय पाल सिंह की उपस्थिति में बुधवार को पर्यटन भवन में राजस्थान पर्यटन नीति और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बन्ध आयोजित बैठक के पश्चात पत्रकारों से बात करते हुए उक्त जानकारी दी।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इससे पूर्व बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर अधिकारियों को बिंदुवार आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्थान पर्यटन नीति तथा राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति में सरलता होनी चाहिए ताकि राजस्थान में पर्यटन को अधिकतम बढ़ावा मिले।

कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में राजस्थान को देश में पहले स्थान पर लाना हमारी प्राथमिकता : कुमावत

जयपुर। पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बुधवार को राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के सभागार में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 13 जिलों में तरल नत्रजन भंडारण हेतु 3000 लीटर के साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि तरल नत्रजन पशु नस्ल सुधार के लिए किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान में काम आता है। तरल नत्रजन की भण्डारण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए राज्य के 16 जिलों में 3-3 हजार लीटर क्षमता के वर्टिकल साइलो पूर्व में स्थापित हो चुके हैं। इस तरह अब राज्य के 29 जिलों में वर्टिकल साइलो की स्थापना हो जाने से तरल नत्रजन भंडारण की कुल क्षमता 93 हजार लीटर हो गई है। जयपुर और उदयपुर के साइलो की क्षमता 6-6 हजार लीटर की है।

■ पशुपालन मंत्री ने तरल नत्रजन भंडारण के लिये 13 जिलों के लिए साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया

को ए आई किट का वितरण भी किया। उन्होंने मंत्री कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करें और कृत्रिम गर्भाधान में राजस्थान को देश में पहला स्थान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। शासन सचिव पशुपालन, गोपालन और मत्स्य डॉ. समित शर्मा ने कहा कि आज दौसा, टोंक, बाड़मेर, सर्वाडीमाधोपुर, बारां, जैसलमेर, जालौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर और चुरू जिलों में 218 लाख रुपये के नवीन वर्टिकल साइलो का लोकार्पण किया गया। 5 अन्य जिलों धौलपुर, सिरौही, झालावाड़, बून्दी और कुचामनसिटी में 3 हजार लीटर की क्षमता वाले साइलो की स्थापना आने वाले दिनों में भारत सरकार से बजट प्राप्त होने पर कर दी जाएगी। इस अवसर पर राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा पशुपालन निदेशक डॉ. आनंद सेजरा, पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. सुरेशचंद्र मीना सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद थे।

राजस्थान में वर्ष 2025-26 में 4.40 लाख करोड़ रु. के ऋण वितरण का आंकलन किया नाबार्ड ने

जयपुर (कांस)। राजस्थान में एकीकृत और सतत ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रु 4.40 लाख करोड़ के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण का अनुमान लगाया है। ऋण की संभावित राशि पिछले वर्ष के अनुमान की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है।

स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2025-26 नाबार्ड राजस्थान



सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने नाबार्ड द्वारा बुधवार को आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार के दौरान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तैयार किए गए स्टेट फोकस पेपर (एसएफपी) का विमोचन किया।

बहुउद्देश्यीय की स्थापना, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, सहकारिता में सहकार पर राष्ट्रव्यापी अभियान और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंकों की मजबूती को शामिल किया है। सहकारिता विभाग की प्रमुख

■ सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने में नाबार्ड का महत्वपूर्ण योगदान : दक

राजीव सिवाच ने स्टेट फोकस पेपर के विषय में बताते हुए कहा कि कुल अनुमानित ऋण संभाव्यता में 47 प्रतिशत कृषि और संबद्ध कार्यों के लिए आंकलित किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 45 प्रतिशत और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कि आवास, शिक्षा आदि के लिए 8 प्रतिशत आंकलित किया गया है। उन्होंने बताया कि एसएफपी में आंकलित ऋण संभाव्यता का उपयोग वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक ऋण योजना तैयार करने के लिए एक आधार दस्तावेज के रूप में किया जाएगा। डॉ. सिवाच ने आगे यह कहा कि कृषि आधारभूत सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऋण संवर्धन और किसानों को किसान उत्पादक संगठनों में संगठित करके कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। सेमीनार के दौरान, राज्य में वर्ष 2024-25 के दौरान सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेख्य कार्य करने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैन्स), जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और कृषक उत्पादक संगठनों को भी सम्मानित किया गया।